

[2023] 10 एस. सी. आर 95:2023 आई. एन. एस. सी 592

ए.

शांतबाई आनंद जगताप और ए. एन. आर. बनाम

जयराम गणपति जगताप और ए. एन. आर. (2012 की सिविल अपील संख्या 5786) 04 जुलाई, 2023

बी.

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923: क्षतिपूर्ति-दावा-प्रत्यर्थी सं. के स्वामित्व वाली जीप चलाते समय सड़क दुर्घटना में रोजगार के दौरान पीड़ित की मृत्यु। 1 – कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा मुआवजे के लिए दावा-न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे का पुरस्कार, केवल वाहन के मालिक के खिलाफ, हालांकि, आदेश निष्पादित नहीं किया गया- अपीलार्थीगण ने तब आयुक्त के समक्ष दावा याचिका दायर की और उसे देरी के साथ-साथ गुण-दोष के कारण खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने दावा याचिका दायर करने में देरी पर निष्कर्षों को बरकरार रखा, हालांकि, मामले के गुण-दोष के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया-अपील पर कहा गया: मृतक और प्रत्यर्थी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध सं। 1 आयुक्त के समक्ष साबित नहीं किया गया, जो कि 1923 के अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए पूरी की जाने वाली मूल आवश्यकता है-साथ ही, आवेदन दायर करने में देरी की माफी के लिए कोई पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया है-इस प्रकार, अपीलार्थीगण कोई मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं-आक्षेपित आदेश में कोई कमजोरी नहीं पाई गई-मोटर वाहन अधिनियम, 1988।

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़ना: 1.1 अपीलार्थी के नेतृत्व में साक्ष्य सं। 1, उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वाहन का मालिक उसके पति का भाई था। यह भी स्वीकार किया गया कि उनके पास सामान्य राशन कार्ड था। वे एक ही संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे। मृतक का वेतन प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया था, हालांकि यह साबित नहीं हुआ था। ऐसा कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि तथ्याकथित नियोक्ता ने स्वामी और सेवक के रिश्ते को स्वीकार किया था। इस न्यायालय के समक्ष भी, अपीलार्थीगण अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख यह

दिखाने के लिए नहीं कर पाए हैं कि मृतक और प्रत्यर्थी के बीच स्वामी और सेवक संबंध मौजूद थे।**1**, अर्थात्, वाहन का मालिक जिसने ए डालने का विकल्प नहीं चुना है।

एफ.

जी.

एच.

95

96 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

सेवा के बावजूद उपस्थिति। वास्तव में, पक्षों के आचरण से अब पता चलता है कि उनका इरादा उल्लंघन करने वाले वाहन से मुआवजे का दावा करने का था। एक सुनियोजित कदम में, न्यायाधिकरण के समक्ष वाहन के मालिक या वाहन की बीमा कंपनी, जिसे मृतक चला रहा था, के खिलाफ कोई दावा नहीं किया गया था। [पारस **12,13**] [99-ई-एच]

बी.

1.2 नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध आयुक्त के समक्ष साबित नहीं हुआ है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, **1923** के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए पूरी की जाने वाली मूल आवश्यकता होने के कारण, अपीलार्थीगण कोई मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हो सकते हैं। [पैरा **14**] [100-बी]

सी.

1.3 अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं स्थापित मामला यह था कि उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करते समय वाहन के मालिक, जो कथित रूप से नियोक्ता है, के खिलाफ किसी भी मुआवजे का दावा नहीं किया था। यही कारण था कि वे **1923** के अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करना चाहते थे। एक बार ऐसा होने के बाद, यह तथ्य उनकी जानकारी में शुरू से ही था, **1923** के अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने में **9** साल की देरी, निश्चित रूप से मुआवजे के पुरस्कार के लिए अपीलार्थीगण द्वारा दावे पर विचार करने के लिए घातक है। वास्तव में, आयुक्त के समक्ष आवेदन **02.08.2004** पर दायर किया गया था, केवल न्यायाधिकरण में कार्यवाही समाप्त होने के बाद **07.02.2003** पर और अपीलार्थीगण निष्पादन में कोई मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया है। इस प्रकार, आक्षेपित क्रम में कोई दुर्बलता नहीं है। [पारस **15,16**] [100-सी-ई]

डी.

ई.

एफ.

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2012 की सिविल अपील सं. 5786।

2009 के एफ. ए. सं. 591 में बंबई उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.04.2010 के निर्णय और आदेश से।

जी.

अब्दुलरहिमान तंबोली, राहुल जोशी, शिवाजी एम. जाधव, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

रवि बख्शी, सुश्री सायमा फिरोज, यश पाल ढींगरा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एच.

97

शांतबाई आनंद जगताप और ए. एन. आर. बनाम जयराम गणपति जगताप और ए. एन. आर. [राजेश बिंदल, जे।] ए.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

राजेश बिंदल, जे।

1. बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा 2009 की पहली अपील में पारित आदेश (आईडी1) ने सांगली में कामगारों के मुआवजे के आयुक्त (संक्षेप में "आयुक्त") द्वारा पारित आदेश (आईडी2) को बरकरार रखते हुए कामगार के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आक्षेप किया गया है।

बी.

2. यह एक ऐसा मामला है जिसमें मृतक मछिंद्र आनंद जगतप के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिनकी जीप नं.17.08.1993 पर MH-10-8363।जीप का स्वामित्व जयराम गणपति जगतप के पास था और इसका बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ किया गया था। दावा इस तथ्य के आधार पर था कि मछिंद्र आनंद जगतप की मृत्यु उनकी नौकरी के दौरान हुई थी, इसलिए, उनके कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजे प्राप्त करने के हकदार हैं। ब्याज और जुर्माने के साथ 1,13,855 का दावा किया गया था। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (संक्षेप में "1923 अधिनियम") के तहत 02.08.2004 पर आयुक्त के पास आवेदन दायर किया गया था।

सी.

डी.

3. आयुक्त ने विलंब के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया। दावा याचिका को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 अधिनियम") की धारा 167 को देखते हुए भी विचारणीय नहीं माना गया था। उच्च न्यायालय ने विलंब के मुद्दे और गुण-दोष के आधार पर कुछ भी नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने पाया कि देरी बहुत अधिक होने के कारण, आयुक्त ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया था। हालाँकि, दावा याचिका को बनाए रखने योग्य माना गया था।

ई.

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें मछिंद्र आनंद जगतप की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी, जब वह जयराम गणपति जगतप (प्रतिवादी संख्या 1) के पद पर थे। दुर्घटना 17.08.1993 पर हुई। इसके तुरंत बाद, जैसा कि सलाह दी गई थी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (जिसे इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) के समक्ष एक दावा याचिका दायर की गई थी जिसका निपटान 07.03.2003 पर किया गया था। उल्लंघन करने वाले वाहन के खिलाफ दावा स्वीकार कर लिया गया। हालाँकि, वाहन का बीमा नहीं होने के कारण, पुरस्कार केवल वाहन के मालिक के खिलाफ पारित किया गया था, जो निष्पादित नहीं हुआ था। इस न्यायालय में दिनांक 01.05.2023 का एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि पुरस्कार को आज तक निष्पादित नहीं किया जा सका है। प्रत्यर्थीगण के खिलाफ कोई दावा नहीं किया गया था। उपरोक्त पुरस्कार के बाद

एफ.

जी.

एच.

98

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया था, जैसा कि सलाह दी गई थी, अपीलार्थीगण ने 02.08.2004 पर आयुक्त के समक्ष दावा याचिका दायर की। इसे देरी के साथ-साथ गुण-दोष के कारण भी अस्वीकार कर दिया गया था। आयुक्त के समक्ष आवेदन दाखिल करने में देरी जानबूझकर नहीं की गई थी। वास्तव में, परिवार में एक युवा कमाने वाले की मृत्यु के बाद मृतक का परिवार ऊँचा और सूखा रह गया था। उच्च न्यायालय को विलंब को माफ करने और

अपीलार्थीगण को राहत देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था। मृतक प्रत्यर्थी संख्या के साथ काम कर रहा था। 1 2000/- के मासिक वेतन पर। अपीलार्थीगण जिस मुआवजे के हकदार होंगे, उसकी गणना 1923 के अधिनियम के तहत निर्धारित सूत्र के संदर्भ में की जानी चाहिए। 5. प्रत्यर्थी नं. के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है। 1/ सेवा के बावजूद नियोक्ता।

बी.

₹

सी.

6. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें मृतक और प्रत्यर्थी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था। 1. वे दोनों एक-दूसरे से संबंधित थे। दावेदार द्वारा यह भी स्वीकार किया गया था कि उसका रोजगार दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसे केवल मुआवजे का दावा करने के लिए बनाया गया था।

डी.

7. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड/प्रासंगिक दस्तावेजों का अध्ययन किया।

ई.

8. अभिलेख पर मौजूद तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मछिंद्र आनंद जगतप की मृत्यु 17.08.1993 पर एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। इसके तुरंत बाद, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने 1993 में एम. ए. सी. टी., हुक्केरी के समक्ष 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत 1993 की एम. ए. सी. पी. संख्या 1458 के साथ एक दावा याचिका दायर की। उसी पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया था, जिसमें 81,600/- के मुआवजे को अपीलार्थीगण को देय होने का आकलन किया गया था। न्यायाधिकरण के निर्णय को अंतिम रूप दिया गया क्योंकि सुनवाई के समय कुछ भी नहीं बताया गया था कि इसे आगे चुनौती दी गई थी। इसके बाद, अपीलार्थीगण ने 1923 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे की मांग करते हुए आयुक्त के समक्ष आवेदन दायर किया। हालाँकि, आयुक्त द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि दावा याचिका को खारिज कर दिया गया था क्योंकि अपीलार्थीगण ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे का दावा करने के विकल्प का प्रयोग किया था और इसलिए वे 1923 के अधिनियम के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकते थे। हालाँकि, तथ्य यह है कि आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा दरकिनार कर दिया गया था और आवेदन को बनाए रखने योग्य माना गया था जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है। आयुक्त ए

एफ.

जी.

एच.

99

शांतबाई आनंद जगताप और ए. एन. आर. बनाम जयराम गणपति जगताप और ए. एन. आर. [राजेश बिंदल, जे।] ए.

देरी के आधार पर भी आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके अलावा नियोक्ता और कर्मचारी संबंध भी मुआवजे का दावा करने के लिए साबित नहीं हुए। उच्च न्यायालय ने दावा याचिका दायर करने में देरी पर आयुक्त के निष्कर्षों को बरकरार रखा। हालांकि, नियोक्ता और कर्मचारी संबंधों के मुद्दे पर कुछ भी चर्चा नहीं हुई।

9. वर्तमान अपील में दो मुद्दे उठते हैं। सबसे पहले, क्या 1923 के अधिनियम के तहत आयुक्त के समक्ष आवेदन दायर करने में लगभग 9 साल और पांच महीने की देरी के लिए पर्याप्त कारण था। दूसरा, उपरोक्त बाधा को पार करने की स्थिति में, क्या नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध साबित हो गया है। 10. हमारी राय में, मृतक और प्रत्यर्थी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध के बारे में मुद्दा नं० 1-जयराम गणपति जगताप पर पहले विचार करने की आवश्यकता है।

बी.

सी.

11. जहाँ तक संबंधों का संबंध है, आयुक्त ने निम्नलिखित मुद्दा तैयार किया था:

डी.

“क्या आवेदक यह साबित करते हैं कि मृतक की दुर्घटना विपक्ष संख्या 1 के साथ उसकी नौकरी के दौरान और उसके बाहर हुई थी?”

12. अपीलार्थी के नेतृत्व में साक्ष्य सं० 1, उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वाहन का मालिक उसके पति का भाई था। यह भी स्वीकार किया गया कि उनके पास सामान्य राशन कार्ड था। वे एक ही संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे। मृतक का वेतन प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया था, हालांकि यह साबित नहीं हुआ था। ऐसा कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि तथाकथित नियोक्ता ने स्वामी और सेवक के रिश्ते को स्वीकार किया था। इस न्यायालय के समक्ष भी, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख यह दिखाने के लिए नहीं किया है कि मृतक और प्रत्यर्थी के बीच स्वामी और सेवक संबंध मौजूद थे। 1, अर्थात्, वाहन का मालिक जिसने सेवा के बावजूद उपस्थिति का विकल्प नहीं चुना है।

ई.

एफ.

13. पक्षकारों का आचरण न्यायाधिकरण के निर्णय से स्पष्ट है जिसमें उल्लंघन करने वाले वाहन से मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से वाहन का मालिक गवाह पेटी में उपस्थित हुआ था और कहा था कि वह मृतक को 2,000/- रुपये का वेतन और 25/- रुपये का दैनिक भत्ता दे रहा था। यदि ऐसा था, तो वाहन के मालिक, जिसे नियोक्ता कहा जाता है, को आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने और नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध को स्वीकार करने से कुछ भी नहीं रोक सका।

जी.

र

एच.

100

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

वास्तव में, पक्षों के आचरण से अब पता चलता है कि उनका इरादा उल्लंघन करने वाले वाहन से मुआवजे का दावा करने का था। एक सुनियोजित कदम में, न्यायाधिकरण के समक्ष वाहन के मालिक या वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया गया था, जिसे मृतक चला रहा था। 14. नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध आयुक्त के समक्ष साबित नहीं हुआ है। हमारी राय में, 1923 के अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए पूरी की जाने वाली मूल आवश्यकता होने के कारण, अपीलार्थीगण कोई मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हो सकते हैं। 15. यहां तक कि आयुक्त यानी 02.08.2004 के समक्ष आवेदन दाखिल करने में देरी के आधार पर भी, इसे खारिज किया जाना चाहिए। अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं स्थापित मामला यह था कि उन्होंने न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करते समय वाहन के मालिक, जो कथित रूप से नियोक्ता है, के खिलाफ किसी भी मुआवजे का दावा नहीं किया था। यही कारण था कि वे 1923 के अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करना चाहते थे। एक बार ऐसा होने के बाद, यह तथ्य उनकी जानकारी में शुरू से ही था, 1923 के अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने में 9 साल की देरी, निश्चित रूप से मुआवजे के पुरस्कार के लिए अपीलार्थीगण द्वारा दावे पर विचार करने के लिए घातक है। वास्तव में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही आयुक्त के समक्ष आवेदन दायर किया गया था और अपीलार्थीगण निष्पादन में कोई मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। आयुक्त के समक्ष आवेदन 02.08.2004 पर दायर किया गया था। इसलिए, हमारी राय में, आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

16. ऊपर वर्णित कारणों से, हम आक्षेपित क्रम में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एफ.

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

जी.

एच.